1	2		4
16	Sarul	Stocks delivered directly from the Rail Head but shown to be delivered from the Warehouse.	The matter is under investigation.
17	Budge-Budge-II	Shortage of STC Oil.	Warehouse Manager, Technical Asstt. One WAG. II and one Chowkidar placed under suspension and departmental proceedings initiated.
18	Virugambakkam	There was shortage in stocks of SAIL Steel.	The matter is under investigation.
19	Dalri	Defalcation of cash.	The services of the Warehouse Manager have been terminated.
20	Ranchi	Irregularity in appointment of H & T Contractor.	Warehouse Manager has been charge sheeted.

Import of deffected wheat

558. SHRI VIREN J. SHAH: Will the Minister of FOOD be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a Canadian consignment of 50,000 tonnes of wheat has been found to contain more husk than grain and unfit for human consumption;

(b) if so, what are the details in this regard;

(c) what action Government have taken in the matter;

(d) how Government propose to dispose of this huge quantity of wheat which is unfit for human consumption; and

(e) what cost the wheat has been be sold through P.D.S.?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD (SHRI KALP NATH RAI): (a) No, Sir.

(b) to (d) Do not arise.

(e) The estimated weighted average CIF cost of the Canadian Wheat works out to US $ 179.08 or Rs. 4657/- M.T. The existing Central Issue Price for wheat ex-FCI depot for distribution through PDS is Rs. 3300/- M.T.

Contribution of Gujarat to Central Pool

559. SHRI ANANTRAY DEVSHANKER DAVE: Will the Minister of FOOD be pleased to state:

(a) what is contribution of Gujarat to the Central Pool of foodgrains during the last three years; and

(b) the details of foodgrains, rice allotted to that State during that period?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD (SHRI KALP NATH RAI): (a) Gujarat does not contribute foodgrains to the Central Pool.

(b) The following quantities of rice and wheat have been allotted to the State Government of Gujarat from Central Pool for Public Distribution System during the years 1990, 1991, 1992 and 1993:—

(In '000 Tonnes)

Year	Allotment of food-grains	
	Rice	Wheat
1990 . . .	330.0	725.0
1991 . .	324.0	944.3
1992 . . .	330.4	780.3
1993 . . . . (Up to March, 93)	103.5	170.5

केन्द्रीय भंडारण के लिये गेहूं का आयात

560. **श्री सोम पाल :**
श्री शिवचरण सिंह :

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार केन्द्रीय भंडारण के लिये और अधिक गेहूं का आयात करने का विचार रखती हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ;

(ग) सरकार किन किन देशों से गेहूं को कितनी-कितनी मात्रा का आयात करने का इरादा रखती है;

(घ) गेहूं का आयात कब तक कर दिये जाने की संभावना है ;

(ङ) क्या सरकार को चालू वर्ष के दौरान आयातित गेहूं घटिया किस्म का होने के विषय में कोई रिपोर्ट मिली है ;

(च) यदि हां, तो ऐसे गेहूं की प्रमात्रा कितनी है और उसे किस देश से आयात किया गया था ; और

(छ) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) जून–अक्तूबर, 1992 के दौरान 29.90 लाख मीटरी टन गेहूं का आयात करने के लिए किए गए ठेके के अलावा गेहूं का कोई आयात करने का प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

(ङ) से (छ) सरकार ने 6–2–93 को प्रकाशित कुछ समचार देखे हैं जिन में यह आरोप लगाया गया है कि कुछ घटिया किस्म का गेहूं प्राप्त हुआ था। निरीक्षण करने पर 1.49 लाख मीटरी टन अमरीकी गेहूं में जीवित घुन पाये गये और इसका प्रधूमन करना आवश्यक था। जहाजों से गेहूं का उतरान करने से पूर्व उसका प्रधूमन कर दिया गया। खाद्यान्नों का परिरक्षण करने के लिये स्वीकृत प्रधूमकों से खाद्यान्नों का प्रधूमन करना एक सामान्य प्रक्रिया है और इसका विशेषतया हमारी जैसी उष्णकटिबंधीय जलवायु में व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है। गेहूं में घुन की मौजूदगी होने के प्रश्न को संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग सहित संयुक्त राज्य अमेरिका की अनाज निरीक्षण एजेंसियों के साथ उठाया गया है और सुधारात्मक उपाय शुरू कर दिये गये हैं। बम्बई सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला, पुणे से गेहूं का परीक्षण करवाया गया था और उन्होंने प्रमाणित किया है कि यह गेहूं खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के उपबंधों के अधीन मानव उपभोग के लिये उपयुक्त है।

Restructing of Lalit Kala Akademi

561. SHRI P. UPENDRA: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether eminent artists have demanded immediate restructuring of the Lalit Kala Akademi; and